



## डजिटल भुगतान सूचकांक

### प्रिलमिस के लिये:

डजिटल भुगतान सूचकांक, अखलि भारतीय चेक ट्रंकेशन प्रणाली

### मेन्स के लिये:

RBI का वकिसात्मक एवं वनियामक नीतिसंबंधी वक्तव्य

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा जारी वकिसात्मक एवं वनियामक नीतिसंबंधी वक्तव्य (Statement on Developmental and Regulatory Policies) में [डजिटल भुगतान](#) संबंधी प्रावधानों की चर्चा की गई है।

## मुख्य बदि:

- RBI द्वारा जारी इस वक्तव्य में डजिटल भुगतानों की सीमा का प्रभावी ढंग से आकलन करने के लिये एक **डजिटल भुगतान सूचकांक** (Digital Payments Index- DPI) प्रारंभ करने की घोषणा की गई है।
- RBI द्वारा जारी यह वक्तव्य क्रेडिट प्रवाह में सुधार, मौद्रिक संचरण को सुदृढ़ करने, वनियामन और पर्यवेक्षण को मज़बूत करने, वित्तीय बाजारों को व्यापक बनाने तथा भुगतान और नपिटान प्रणाली में सुधार के लिये वभिन्न वकिसात्मक और वनियामक नीति उपायों को नरिधारति करता है।

## क्या है डजिटल भुगतान सूचकांक?

- RBI द्वारा दिये गए वकिसात्मक एवं वनियामक नीतिसंबंधी वक्तव्य के अनुसार, भारत में डजिटल भुगतान तेज़ी से बढ़ रहा है। RBI समय-समय पर भुगतान के डजिटलीकरण की सीमा का प्रभावी ढंग से आकलन करने के लिये एक समग्र 'डजिटल भुगतान सूचकांक' का नरिमाण करेगा।
- DPI कई मापदंडों पर आधारति होगा और वभिन्न डजिटल भुगतान के तरीकों की पहुँच और गहनता को सटीक रूप से आकलति करेगा।
- DPI को जुलाई 2020 से प्रारंभ कथिा जाएगा।

## भुगतान एवं नपिटान प्रणाली संबंधी अन्य प्रावधान:

- **डजिटल भुगतान प्रणाली के लिये स्व-वनियामक संगठन (Self-Regulatory Organisation- SRO) की स्थापना की रूपरेखा:**
  - RBI द्वारा जारी वकिसात्मक एवं वनियामक नीतिसंबंधी वक्तव्य के अनुसार, भुगतान तंत्र में डजिटल भुगतान में पर्याप्त संवृद्धि और संस्थाओं की भुगतान प्रणाली में प्राप्त परपिक्वता सहति संस्थाओं के व्यवस्थति परचालन के लिये स्व-नियामक संगठन होना आवश्यक है।
  - RBI धन की सुरक्षा, ग्राहक संरक्षण और मूल्य नरिधारण की सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अप्रैल 2020 तक डजिटल भुगतान प्रणाली के लिये एक स्व-नियामक संगठन की स्थापना की रूपरेखा तैयार करेगा।
- **अखलि भारतीय चेक ट्रंकेशन प्रणाली (Pan India Cheque Truncation System-CTS):**
  - चेक ट्रंकेशन प्रणाली वर्तमान में देश के प्रमुख समाशोधन गृहों में ही परचालति है तथा इसने अच्छी तरह से स्थरि होकर दक्षता हासलि की है।
  - इसको देखते हुए एक अखलि भारतीय चेक ट्रंकेशन प्रणाली को सतिंबर 2020 तक परचालति कर दथिा जाएगा।

## अन्य प्रयास:

- बैंकगि नयामक संस्थाएँ और सरकार डजिटल वॉलेट्स, इंटरनेट बैंकगि, क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड जैसी कैशलेस भुगतान प्रणालयिों को अपनाने की सुवधि पर काम कर रही है।

- सरकार ने हाल ही में रुपे डेबिट कार्ड और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से किये जाने वाले भुगतान पर [मर्चेंट डिसकाउंट रेट \(Merchant Discount Rates-MDR\)](#) को समाप्त कर दिया है।

डजिटल इंडिया एक ऐसा वचिार है जसिको व्यावहारकि रूप में अपनाना आवश्यक है लेकनि इसके लयि कारगर उपाय करने होंगे, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को और भी अधिक गतमिन और समृद्ध बनाया जा सके।

## स्रोत- लाइव मटि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/digital-payments-index>

